THE BIHAR LEGISLATIVE ASSEMBLY DEBATES.

Wednesday, the 15th September, 1937.

Proceedings of the Bihar Legislative Assembly assembled under the provisions of the Government of India Act, 1935.

The Assembly met in the Assembly Chamber at Patna on Wednesday, the 15th September, 1937, at 11 A.M., the Hon'ble the Speaker in the Chair.

UNSTARRED QUESTIONS AND ANSWERS.

PETITION FROM TENANTS OF VILLAGES SITUATED ON THE NORTH SIDE OF RIVER SIKRAHNA FOR REMISSION OF RENT.

108. Mr. BAIDYANATH MISRA: Will Government be pleased to state—

(*a*) whether it is a fact that the tenants of the villages situated on the north side of the river Sikrahna in the police-stations Sugauli and Motihari, filed petitions before the Collector of Champaran and the Manager of the Bettiah Raj under Court of Wards for the remission of rent for last year and the previous years ;

(*b*) if the answer to clause (*a*) be in affirmative, whether the remission of rent has been granted to the tenants ; if not, why not ;

(*c*) whether they propose to make a thorough enquiry into the situation and grant an adequate remission in rent to the tenants of the area in question ?

Mr. KRISHNA BALLABH SAHAY: (*a*), (*b*) and (*c*) Information is being collected and will be made available to the hon'ble member when obtained.

Mr. HARIVANS SAHAY : Will Government make the answer available in this session or after this session ?

Mr. KRISHNA BALLABH SAHAY : In this session, Sir, and it will be laid on the table.

मिडल स्कूल, २,४२० प्राइमरी स्कूल और २४ स्पेशल स्कूल, सरकारी मदद से चलरहे थे, और २५६ स्कूल गैर सरकारी ढंग से। सन् १९३६ ई० में प्राइमरी स्कूल की संख्या में बढ़ने के बदले ३४ और घट गये। स्पेशल स्कूल ३ और घट गये, और गैर सरकारी स्कूल भी २७ और घट गये। स्त्रियों की संख्या १ करोड़ ८८ लाख दोनों सूबों बिहार और उड़ीसा को मिलाकर १९३५-३६ ई० में थी। उनके अन्दर कुल इतने ही स्कूल थे जो बढ़ने के बदले और घट रहे हैं। यह बड़े ही खेद की बात है।

बिहार की स्त्रियां धीरे-धीरे समाज और देश की सेवा में आगे बढ़ रही हैं। यदि उन में शिक्षा का प्रचार अच्छी तरह किया जाय, तो वे और सूबों से किसी तरह पीछे न रहेंगी। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि वह स्त्री-शिक्षा की ओर अब भी तो पूरा-पूरा ध्यान दे।

The Hon'ble Dr. SAIYID MAHMUD:

مجھے اسکے متعلق کہنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے - ہماری بہنوں کو معلوم ہونا چاہئے کہ گورنمنٹ عورتوں کی تعلیم کی طرف پوری توجہ کررہی ہے ۲۳ تاریخ کو انکی رائے معلوم کرنے کیلئے کانسل میں جتنی بہنیں ہیں انہیں ایک جلسہ میں دعوت دی گئی ہے اور بھی دیگر بہنوں کو بلایا گیا ہے کہ وہ تجویز پیش کریں کہ اس صوبہ میں عورتوں کی تعلیم کے لئے کیا کیا کرنا چاہئے - میں یقین دلاتا ہوں کہ گورنمنٹ اس مسئلہ کی طرف اپنی پوری توجہ کررہی ہے -

Srimati SARASWATI DEVI: Sir, I beg leave of the House to withdraw my motion.

The motion was, by leave of the Assembly, withdrawn.

CONVERSION OF SECONDARY SCHOOLS IN DISTRICT HEADQUARTERS INTO TECHNICAL SCHOOLS.

Mr. MUHAMMAD SHAFI: I beg to move:

That the provision of Rs 6,83,329 for "Government secondary schools for boys—voted" be reduced by Re. 1.

میں بغیر کسی تقریر کے اس تجویز کو پیش کر دینا چاہتا ہوں -
اور حکومت سے تشفی بخش جواب کا متمنی ہوں -

The Hon'ble Dr. SAIYID MAHMUD:

یہ تجویز نہایت معقول ہے - جہانتک گورنمنٹ کا تعلق ہے یہ سوال اسکے سامنے پیش ہے لیکن ظاہر ہے کہ ابھی فیصلہ نہیں ہوا ہے کہ کسقدر تکنیکل اسکول زیادہ بڑھا دئے جائیں - گورنمنٹ اسپر غور کر رہی ہے کہ کہاں تک تکنیکل تعلیم میں وسعت دی جائے -

Mr. MUHAMMAD SHAFI: Sir, I beg leave of the House to withdraw my motion.

The motion was, by leave of the Assembly, withdrawn.

FREE AND COMPULSORY PRIMARY EDUCATION IN RURAL AREAS.

BARA LAL KANDARP NATH SHAH DEO:

Sir, I beg to move:

That the item of Rs. 29,87,653 for "Recurring grants to local bodies for primary education—voted" be reduced by Re. 1.

Sir, I wanted to write in my cut motion the words "Chota Nagpur" but Chota Nagpur has been left out and I want specially to deal with it. Chota Nagpur, you know, is a backward area and most of the people there are illiterate and the reason that the people are backward is due to illiteracy and which I think is a thing for Government to take care to remove.

Mr. JAMUNA KARJEE: On a point of order, Sir, we cannot hear the hon'ble member's speech and it is better if he moved his motion and did not deliver any speech at all.

Mr. PRABHUNATH SINHA: He is following his own leader.

Mr. CHANDRESHVAR PRASHAD NARAYAN SINHA: May I know, Sir, what the hon'ble member means by saying "he is following his own leader"? Does he mean to reflect something on me? If he does, I would like you, Sir, to make that point clear.

The Hon'ble the SPEAKER: What does the hon'ble member mean by his remarks?

Mr. PRABHUNATH SINHA: I mean to say that as his leader speaks in a very low tone, so does he.

The Hon'ble the SPEAKER: Such remark should not come from a responsible member of this House about another responsible member. This is absolutely undesirable.

BARA LAL KANDARP NATH SHAH DEO: Sir, if I am permitted to speak in Hindi, I can speak more loudly.

The Hon'ble the SPEAKER: Yes, you can speak in Hindi.

BARA LAL KANDARP NATH SHAH DEO :

सभापति महोदय, छोटा नागपुर में बहुत से लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं। यही कारण है कि छोटा नागपुर एक backward area समझा जाता है। छोटा नागपुर में कहा जाता है कि aborigines class के लोग रहते हैं जो अपढ़ हैं लेकिन मेरा ख़्याल है ; कि जो non-aborigines class के लोग हैं वे भी तो पढ़े लिखे नहीं हैं। इसी कारण से उन लोगों को तरह २ को तकलीफें उठानी पड़ती हैं जैसे कि उन लोगों को मुकद्दमे में Subdivisional Officer की कचहरी में जाना पड़ता है या दूसरे आफिसर की कचहरी में जाना पड़ता है तो वहां भी उन लोगों की यह हालत है कि वे लोग वकील और मुख्तारों के ताईदों तथा अन्य काम करनेवालों से ठगे जाते हैं। आज कल उन लोगों के पैसे इस तरह से बहुत बर्बाद होजाते हैं। इसलिये छोटा नागपुर के लोगों का पहला अर्ज़ यह है कि उन लोगों के लिये शिक्षा का प्रबन्ध होना चाहिये। अगर उन लोगों को निःशुल्क शिक्षा नहीं दी जाय तो उन के लिये primary शिक्षा compulsory और free कर दी जाय। यह बहुत ही ज़रूरी है। हम Christian Missionaries के लोगों को धन्यवाद देते हैं जिन लोगों ने छोटा नागपुर के लोगों को थोड़ी बहुत शिक्षा दी है। लेकिन उन में सबसे बड़ा दोष यह है कि शिक्षा देते समय खास कर उन aborigines को जो Christian हैं उनपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। जो लोग उन के भुलावे में नहीं आते हैं उन लोगों को अपने स्कूल से निकाल देते। यदि रखते हैं तो भी जो privilege Christian को देते हैं दूसरों को नहीं देते हैं। छोटा नागपुर में जनसंख्या के मुताबिक ज़्यादा स्कूल नहीं है। छोटा नागपुर की जनसंख्या समूचे बिहार प्रांत का एक तिहाई है। लेकिन तोभी छोटा नागपुर में area और population के हिसाब से स्कूल नहीं है। जो कुछ भी वहां थोड़ा बहुत स्कूल है वह भी इतनी दूरी पर गावों में है कि वे लोग अपने लड़कों को वहां पढ़ने के लिये नहीं भेज सकते हैं। इसलिये उन लोगों के लड़के नहीं पढ़ सकते हैं। फिर भी जब उन लोगों को रहने के लिये घर नहीं है और खाने के लिये अन्न नहीं है तब ऐसी अवस्था में इतनी दूर पर अपने लड़के को भेजकर पढ़ाना बहुत मुश्किल है। वहां जो स्कूलें खुलते हैं उसका परिणाम यह होता है कि Education Code के मुताबिक Education Officer चन्द

ऐसे २ अड़चनें रख देते हैं जिससे उनको स्कूल नहीं चल सकते हैं। इसलिये Education Code में कम से कम यह होना चाहिये कि स्कूल का नम्बर बढ़ा दिया जाय। अगर उसको न बढ़ाया जाय तो जो charitable schools खोले जायें उनमें किसी तरह की अड़चनें न हो और Government उसमें मदद करे।

दूसरी बात यह है कि primary schools में ऐसे २ लड़के आते हैं जिनको किताब, पेन्सिल और कागज़ नहीं रहता है। रांची म्युनिसिपेलिटी की ओर से वहां के स्कूल के गरीब लड़कों के लिये किताब, कागज़ और पेन्सिल दी जाती है। इसलिये वहां के गरीब लड़कों को बहुत सुविधा है। अगर district board के सभी स्कूलों में कागज़, किताब और पेन्सिल दी जाय तो गरीब लड़कों को इससे बहुत सुविधा होगी।

District board schools के अलावे Christian Missionaries वालों के भी सभी तरह के schools हैं; लेकिन तोभी ये सब स्कूल वहांवालों की मांग पूरी नहीं करते हैं। इसका कारण यह है कि Christian Missionaries वाले अपने स्कूलों में सिर्फ Christian लड़को ही अधिक से अधिक सुविधा देते हैं। Aborigines और non-aborigines के लड़कों पर कुछ भी ध्यान नहीं देते हैं। District board जहां इन स्कूलों को aid देती है वहां उनको चाहिये कि मोशन का ध्यान इस ओर आकर्षित करें ताकि वे लोग क्रिश्चन के सिवाए दूसरे लोगों पर भी ध्यान दें और उनके लिये भी सुविधा कर दें। छोटा नागपुर के लोगों को अपढ़ रहने का यही एक प्रधान कारण है। Education के विषय में यह बहुत ज़रूरी है कि primary education पास करने के बाद उन लोगों को काम नहीं मिलता है और वे लोग बेकार रहते हैं। इसलिये हम समझते हैं कि primary education के साथ ही साथ Cotlage Industries, Spinning, Weaving, Handicrafts, Potteries, Wooden toys और Agriculture की भी पढ़ाई पर विशेष ध्यान देना चाहिये। छोटा नागपुर में रूई बहुत पैदा होती है जिससे कपड़े बन सकते हैं। वहां के लोग ज़्यादातर वहीं के कपड़े बने हुए पहिनते हैं। इसलिये अगर primary schools में कपड़ा बुनने का काम सिखाया जाय तो लड़कों को बहुत फ़ायदा हो सकता है। इसके अलावे बहुत सी लकड़ी की चीज़ें वहां

बनायी जाती है जैसे छोटा नागपुर में बहुत से लकड़ी के छोटे २ खिलौने बनाये जाते हैं। यह भी अगर लड़कों को सिखलाया जाय तो उन लोगों के भविष्य जीवन में बहुत सहायक होगा। वहां तो agriculture की शिक्षा देनी चाहिये। क्योंकि वह कृषि प्रधान देश है। इसलिये इसमें उन लोगों को ऐसी शिक्षा देनी चाहिये जिससे वे लोग scientific तरीके से खेती बारी कर सकें और उन लोगों को उसी में ज़्यादा फ़ायदा होगा।

अब मैं लड़कियों की शिक्षा के विषय में कुछ कह देना चाहता हूं। इसके बारे में जो कुछ सरस्वती देवीजी ने कहा है उसको मैं समर्थन करता हूं। लड़कियों की शिक्षा बहुत ज़रूरी है। छोटा नागपुर के रांची जिले में लड़कियों का स्कूल इस प्रान्त के और ज़िलों से कम है; लेकिन वहां के area और population के मुताबिक कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। जिन घरों की स्त्रियां पढ़ी लिखी होती हैं उनका भविष्य जीवन बहुत ही अच्छा होता है। इसलिये वहां के लड़कियों की शिक्षा की ओर Government को ध्यान देना चाहिये।

लड़कियों की शिक्षा भी अगर compulsory कर दी जाय तो बहुत अच्छा होगा। उनकी शिक्षा और लड़कों की शिक्षा में बहुत अन्तर है। उनको रसोई बनाने, handicrafts, needle work और embroidery की शिक्षा देनी चाहिये; क्योंकि अभी जो हमारे घरों में कपड़े सीने की ज़रूरत पड़ती है अगर घरों की स्त्रियां सीने का काम जान जायें तो उससे बहुत कुछ खर्चा बच सकता है। घरों से ही मोजा और गंजी वगैरह का काम चल सकता है। बहुत सी स्त्रियां भोजन बना लेने के बाद दिन भर बैठी रहती हैं। उन लोगों को पांच छः घंटे समय रोज़ बेकार ही बीतते हैं।

अगर वे लोग उस समय को काम में लायें तो बहुत कुछ काम चल सकता है। मैं अन्त में यह कहना चाहता हूं कि जितने colleges, high schools और primary schools हैं उनमें धार्मिक विषय पर शिक्षा नहीं दी जाती है। धार्म्मिक शिक्षा के लिये अगर कुछ समय रख दिया जाय तो बहुत ही अच्छा होगा। हम समझते हैं कि करीब २ बीस, पचीस मिनट तक धार्म्मिक विषय पर शिक्षा देनी चाहिये। Higher education

के सम्बन्ध में मुझे इस समय विशेष कुछ कहना नहीं है पर यदि fund provide करे तो secondary schools खोले जाय तो अच्छा होता। अभी अगर public की ओर से यह स्कूल खोला जाता है तो उसमें भी अड़चनें आ जाती हैं। Education Department के लोग कहते हैं कि अच्छे C. T. teacher नहीं हैं, घर का नाप ठीक नहीं है आदि इसी तरह से कितनी किस्म की शिकायतें होती हैं। इन सब अड़चनों को Education Code से हटा दी जाय और Education Department के जो आफ़िसर हों वे इन बातों की ओर ध्यान दें कि इन स्कूलों के खुलने में कम अड़चन पड़े तो इससे बहुत ही काम चल सकता है और लोगों को बहुत फ़ायदा पहुंच सकता है।

Mr. VINDHYESHVARI PRASHAD VARMA : Sir, I make no apology for not being able to resist the temptation of speaking on this cut motion. The subject is so important, the subject is so useful.

Dr. Sir GANESH DUTTA SINGH : May I know, Sir, whether the discussion is regarding primary education in Chota Nagpur or primary education in general ?

The Hon'ble the SPEAKER : It is regarding primary education in general.

Mr. RAMCHARITRA SINGH : But the hon'ble member spoke of rural areas only.

Mr. RAMESHVAR PRASHAD SINHA : May I suggest, Sir, that nos. 239 and 243 which relate to the same subject may be taken up together ?

The Hon'ble the SPEAKER : If there are other speakers on the municipal areas also, then I will ask Mr. Shafi to speak.

Mr. VINDHYESHVARI PRASHAD VARMA: Then I will confine myself to the rural area.

Mr. SARANGDHAR SINHA: Both motions may be permitted to be discussed together, as they relate to the same subject.

The Hon'ble the SPEAKER: Yes, both may be discussed together.

Mr. VINDHYESHVARI PRASHAD VARMA: If more than sufficient time is taken up by the mover, then I will be deprived of my right.

Mr. MUHAMMAD SHAFI :

جناب صدر - اگر آپ تقریروں کی تعداد ملاحظہ فرمائینگے تو معلوم ہوگا که میں بہت کم آپکو تکلیف دیتا ہوں - اس وقت میں صرف پانچ منٹ لونگا -

It will not be lawyers' minute.

Mr. DEVENDRA NATH SAMANTA: There are two motions standing in my name, Sir, and I think they relate to subjects similar to the subject under discussion and I may be permitted to make my submission.

The Hon'ble the SPEAKER: Mr. Shafi may move his motion.

COMPULSORY PRIMARY EDUCATION IN MUNICIPAL AREAS.

Mr. MUHAMMAD SHAFI: Sir, I beg to move:

That the provision of Rs. 30,74,948 for "Primary Education" be reduced by Re. 1.

میں زیادہ تقریر نہیں کرونگا - میں اس موقعہ پر حکومت کے خیال سے واقف کرنا چاہتا ہوں - میں چاہتا ہوں کہ ابتدائی تعلیم تمام صوبہ میں عام اور جبریہ ہو لیکن اگر حکومت کے پاس ابھی کافی روپیہ نہیں ہے تو شروع کے لئے بہت مناسب ہوگا کہ ہر ضلع میں کم از کم ایک جگہ ابتدائی جبریہ تعلیم کا اجرا ہو جائے - میونسپلٹی میں یہ کام بہت آسانی سے شروع کیا جا سکتا ہے - کیونکہ ایسے رقبہ میں کافی تعداد میں ابتدائی اور ٹونوی اسکول و مدارس ہیں اور آبادی ایک جا ہے - میرا خیال ہے کہ وہاں کچھ زیادہ دقت نہ ہوگی - اگر ہر ضلع کے ایک شہری آبادی کو اسکے لئے منتخب کر لیا جائے تو بہتر ہوگا - اس اصول پر کام شروع کرنے سے کسی ضلع کے لوگوں کو شکایت نہ ہوگی اور اسکے علاوہ صوبہ کے متفرق حصوں میں جبریہ ابتدائی تعلیم کے جاری ہونے سے اس پاس کے لوگوں کے لئے ایک نمونہ بھی ہوگا اور متفرق مقامات کا تجربہ بھی ہوگا - جو صوبہ کے صرف ایک گوشہ میں تجربہ کرنے سے حاصل نہ ہو سکیگا - اگر اسطرح سے یہ کام شروع کیا گیا تو حکومت کو شہری حلقہ میں زیادہ خرچ کرنا نہ پڑیگا - میں امید کرتا ہوں کہ حکومت جلد اسکی طرف متوجہ ہوگی -

Mr. VINDHYESHVARI PRASHAD VARMA: I will take up with your permission, Sir, the question of the introduction of free and compulsory primary education in the municipal areas of the province. Let us first of all have an idea of the whole problem. The total male population of the municipalities of the province is 8 lakhs and odd. The total female population of the municipalities of the province is 6 lakhs and odd. If we take both the questions together of introducing free and compulsory primary education for boys and girls at the same time, it would unnecessarily complicate the whole problem. Therefore, in order to make a beginning the hon'ble gentleman who has moved his cut motion would like to confine it to the education of boys only and

that I think would be a very prudent step on the part of the Government also.

Now, let us then take up the question of introducing it so far as the boys in the municipal areas are concerned. There are 8 lakhs of males inhabiting these areas. If we refer to the Census Reports and also to the Education Code, we would find that 10 per cent of the male population has been taken to be the basis for calculation of students likely to read or likely to attend in the primary schools between the ages of 6 and 10. Then calculating at that rate, the total number of boys we shall have to educate would be 80,000. Now the Education Code prescribes a very high scale for making calculation of the expenditure on this education. It fixes Rs. 11 per head for introducing any scheme of free and compulsory primary education. This, I submit, is a very high scale. It may be reduced to Rs. 6 or Rs. 7 per head. If we take Rs. 7 to be the rate per head of the pupils to be educated, the cost would come to about 5 lakhs 64 thousand ; or if we take Rs. 6 to be the rate, the total cost would be 4 lakhs 83 thousand. If we take Rs. 6 to be the rate and if we take 30 pupils to a teacher, it will come to about Rs. 180 per year. Dividing it by 12 it works out at the rate of Rs. 15 per month for every school of one teacher or per teacher in a school with more than one teacher. So, that would not be a very unsatisfactory rate to begin with. If we take Rs. 6 to be the standard for every pupil, then we have Rs. 4 lakhs 83 thousand to spend. Out of this under the existing rules the municipalities are required to contribute ⅓rd of the total expenditure. We know there is an Act,—the Bihar and Orissa Primary Education Act—which provides for making primary education compulsory. If we follow the rules in force at present, the municipalities would be required to contribute ⅓rd of the total expenditure. I may take it that some of the municipalities may not be able to contribute as much ; but granting that there are poor municipalities which may require concessions from the Government, a lakh of rupees may easily be contributed by them. Then the expenditure is reduced to 3 lakhs and 83 thousand. I have ascertained from the Secretariat and I have been informed that one lakh and sixty-one thousand is at present being contributed by the Government for the education of boys in the primary classes. This is all given to the local bodies of course. This one lakh sixty-one thousand and odd includes some expenditure for the education of girls also, and in addition to this there is a special grant of Rs. 10,000 given for the education of girls. So, roughly we may take one and a half lakhs to be the contribution by Government to the municipalities.

The Hon'ble the SPEAKER : How many minutes does the hon'ble member want still to take to make his submissions ?

Mr. VINDHYESHVARI PRASHAD VARMA : I will finish my speech by five minutes to five, Sir.

The Hon'ble the SPEAKER : Then how many minutes could be given to Government for their reply ? Guillotine will have to be applied to

all demands just after five o'clock. Therefore, if the hon'ble members want to hear the reply of Government, time must be given to them for that.

Dr. Sir GANESH DUTTA SINGH : I think I will not have time to move my motion, but if you permit me, Sir, I would like to make just one suggestion with regard to the primary education.

Mr. VINDHYESHWARI PRASHAD VARMA: We have to find out Rs. 3 lakhs 83 thousand. At present the Government is giving to the local bodies a lakh and a half for the primary education of boys. So the result is that two lakhs and a quarter have to be found by Government for introducing free and compulsory primary education for boys within all the municipalities of the province. Now this amount can be very easily met. The first taxation proposal that we have made in this legislature related to the entertainments within the municipalities. The temporary and permanent residents shall have to contribute and I say it is all honour to the municipalities of the province that they have begun like this and the proceeds or the fruits of this taxation must go to the municipalities and it is estimated that about 2 lakhs or more would be received from this source. There is no time to be lost. Under the primary Education Act about six months' time has to elapse between the presentation of the application for notification and the actual notification. If we want to introduce free and compulsory primary education from April 1938, a circular has to be sent by the Education Department at once that all the municipalities should pass a resolution, at their meetings, at once with a view to introduce it and Government would be prepared to help them. This is with respect to the municipalities.

Now with respect to the rural areas, the subject is simply stupendous. I may say it is staggering. The very baffling nature of the problem would be apparent if I were to detain you for a few minutes for giving you some figures. At present about 6 lakhs 63 thousand students are receiving education. Now the total number of pupils whom we shall have to educate would be about 16 lakhs and odd. The balance would be about 9 lakhs. The number of teachers required at the rate of 30 pupils to a teacher would be about 32 thousand. Now various suggestions have been thrown out in the country. The fact is that the problem is puzzling the best brains. Professor Shah has suggested conscription and Mahatma Gandhi has given his blessing to this scheme. By conscription in the province I think we will not be able to get more than 10 thousand teachers every year, Some 6 to 7 thousand teachers will be turned out of schools and there would be 3 thousand able-bodied qaulified pensioners. They also would receive some allowance, say, about Rs. 10 or Rs. 15. This will cost a good deal and for Rs. 10 or 15 a month, we can have any number of teachers without conscriptions. Now all this would involve an expenditure of not less than 38 lakhs and more. What is to be done ? Are we to leave this subject or have we to do something. I suggest one method of taxation and that is we may collect *mansera* or a s cer in a maund. This would be according to the ancient system. We accepted gifts from charitably disposed people. Boys and students went round for alms and with the collections, the schools were run. I know that some

people will laugh at this idea but many people know the system of *mansera*, i.e., 1-40th in every maund and this may be collected at the threshing floor by the Union Presidents. This would be a taxation not on the agricultural income, but on the corpus of agricultural produce to the extent of 1-40th or 20 per cent of the actual produce. This would give us sufficient money to introduce free and compulsory primary education which is the crying need of the day and so urgently required.

Dr. Sir GANESH DUTTA SINGH : There is only one thing which I like to bring to the notice of the Prime Minister. There is a cry for both male and female education from every corner. For the sake of education health is sacrificed. We do not want primary education or any education for our children at the sacrifice of their health. It is much better that our boys should remain ignorant than that they should lose their health by such education. I have a cutting from the *Amrita Bazar Patrika* containing the opinion of the Minister of Madras. I have nothing more to add.

The Honble Dr. SAIYID MAHMUD :

حضور والا - یہ ایک ایسا مضمون ہے کہ اس پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے - جہاں تک کانگریس کمیٹی کا تعلق ہے پرائمری تعلیم کی طرف زیادہ توجہ کرنیکا خیال رکھتی ہے - اس لئے جہانتک موجودہ گورنمنٹ کا تعلق ہے وہ نہایت محنت کے ساتھہ primary education کے سوال پر غور کر رہی ہے - Experts سے مشورے لے رہی ہے اور صوبوں سے بھی مشورے لے رہی ہے ظاہر ہے کہ اس میں وقت لگیگا - اور ابھی تک میں نہیں بتلا سکتا کہ کیا system اختیار کیا جائیگا لیکن گورنمنٹ اس مسئلہ کی طرف غور و بچار کرکے primary تعلیم اس صوبہ میں جاری کرنا چاہتی ہے -

BARA LAL KANDARAP NATH SHAH DEO : Sir, I beg leave of the House to withdraw my motion.

The motion was, by leave of the Assembly, withdrawn.

Mr. MUHAMMAD SHAFI : Sir, I beg leave of the House to withdraw my motion.

The motion was, by leave of the Assembly, withdrawn.

The Hon'ble the SPEAKER : The question is :

That this Assembly do assent to a demand of Rs. 69,08,887 to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1938, in respect of "Education".

The motion was adopted.